शिक्षकों की जल्दी भर्ती

सुदृढ़ शिक्षा तंत्र के बिना कोई भी देश विकास की राह पर मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है. अनेक क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद देश में शिक्षा की बेहतरी पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है. संसाधनों और पाठ्यक्रमों के अभाव का क्या रोना, जब 48 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ही शिक्षकों के लगभग पांच हजार पद रिक्त हैं. नये केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जहां 48 फीसदी पद खाली हैं, वहीं इलाहाबाद और दिल्ली जैसे पुराने व प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में रिक्तियों का आंकड़ा क्रमशः 64.44 और 47.7 फीसदी है. इन तथ्यों से राज्य-स्तरीय एवं अन्य केंद्रीय संस्थानों की हालत का अनुमान लगाया जा सकता है. ज्यादातर संस्थानों में शिक्षण-प्रशिक्षण संविदा और तदर्थ शिक्षकों के भरोसे है. पर इस स्थिति में बहुत जल्दी सकारात्मक परिवर्तन की आशा है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देशभर के संस्थानों को छह महीने के भीतर सभी खाली पदों को भरने का निर्देश दिया है. आयोग के अंतर्गत 900 से अधिक विश्वविद्यालय और 40 हजार से अधिक कॉलेज हैं. यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हर स्तर पर भर्ती प्रक्रिया की निगरानी की जायेगी. अगर कोई संस्थान इस निर्देश पर अमल नहीं करेगा, तो उसके अनुदान को रोकने की चेतावनी भी जारी की गयी है. पिछले वर्ष जुलाई में सरकार ने संसद में कहा था कि स्वायत्त संस्थान होने के कारण शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों की है. लेकिन रिक्तियों की बड़ी संख्या तथा तदर्थ व संविदा शिक्षकों को रखने का चलन यह इंगित करता है कि न तो संस्थानों ने गंभीरता दिखायी है और न ही यूजीसी ने जरूरी दबाव बनाया. बहरहाल, अगले छह माह में हजारों शिक्षकों की स्थायी बहाली 3.7 करोड़ छात्रों के भविष्य को संवारने की दिशा में बड़ी पहल हो सकती है. वर्तमान में देश में उच्च शिक्षा और शोध की दिशा में व्यवस्थागत सुधार की बड़ी दरकार है. साथ ही, इस क्षेत्र में सावर्जनिक निवेश को भी बढ़ाना होगा. प्रस्तावित नयी शिक्षा नीति में इन पहलुओं पर ध्यान दिया गया है. जो देश उच्च शिक्षा पर अधिक खर्च करते हैं, उनके संस्थान वैश्विक सूची में अग्रणी होते हैं. ज्ञान-विज्ञान के हर क्षेत्र में भारतीय मेधा का लोहा दुनिया मानती है, परंतु शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों की सूची में हमारे विश्वविद्यालय दूर-दूर तक नजर नहीं आते हैं. आखिर उच्च शिक्षा में पांच लाख रिक्त पदों के साथ बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल भी नहीं की जा सकती हैं. केंद्र सरकार ने अपने पहले सौ दिनों के शैक्षणिक एजेंडे में खाली पदों पर बहाली को प्राथमिकता देकर अत्यंत सराहनीय पहलकदमी की है. इसके साथ 10 अन्य उत्कृष्ट संस्थानों को दर्जा दिये जाने की कार्य-योजना भी है. उम्मीद है कि यूजीसी के निर्देश के अनुसार सभी संस्थान निर्धारित समय पर नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे. इससे न सिर्फ छात्रों को पूर्णकालिक शिक्षक मिलेंगे, बल्कि समूचे शैक्षणिक परिवेश में नयी ऊर्जा का संचार भी होगा.

अगले छह माह में हजारों शिक्षकों की स्थायी बहाली 3.7 करोड़ छात्रों के भविष्य को संवारने की दिशा में बड़ी पहल हो सकती है.

दूसरे कार्यकाल में विदेश नीति

पुष्पेश पंत
वरिष्ठ स्तंभकार
pushpeshpant@gmail.com

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने शपथ-ग्रहण समारोह से ही यह संकेत दे दिया था कि भारतीय राजनय को गतिशील बनाकर वह राष्ट्रहित को प्राथमिकता देंगे. उनके पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह दूसरे कार्यकाल तक पस्त हो चुके थे और अपनी विश्वसनीयता खो चुके थे. ऐसा जान पड़ता था कि पाकिस्तान हो या चीन, भारत की सुरक्षा को अक्षत रखने में वह और उनकी सरकार अक्षम है. अर्थशास्त्री के रूप मे उनकी 'ख्याति' कवच का काम करने में असमर्थ रही. पर यह सुझाना तर्कसंगत नहीं है कि मात्र उनके लकवाग्रस्त प्रदर्शन की तुलना में ही मोदी की उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं.

असाधारण सक्रियता के साथ मोदी ने दुनियाभर के देशों के दौरे किये, घर पर शाही मेहमानों का स्वागत किया और भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर निश्चय ही नये विकल्प उद्घाटित किये. आवश्यकतानुसार ही चीन और पाकिस्तान के प्रति सख्ती या नरमी का रुख अपनाया गया तथा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे अक्सर बेचैन पड़ोसियों को तुष्टीकरण के बिना कमोबेश संतुष्ट रखा जा सका. कांग्रेसी निरंतर 'सर्जिकल स्ट्राइक' के दावों को झुठलाने में लगे रहे, पर पांच साल के कार्यकाल में शर्म-अल-शेख जैसा फजीता नहीं हुआ. बहरहाल, यह सब अतीत-व्यतीत है. अहम सवाल यह है कि मोदी के दूसरे कार्यकाल में विदेश नीति तथा राजनय के क्षेत्र में निरंतरता और परिवर्तन का क्या संतुलन बैठाया जा सकता है.

इस बार शपथ ग्रहण समारोह के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को नहीं न्यौता गया, हालांकि उन्होंने मोदी को बधाई देने में देर नहीं लगायी थी. दक्षेस (सार्क) से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और श्रीलंका सस्नेह आमंत्रित मेहमान थे. यह साफ संदेश था कि इस बार पाकिस्तान के कारण सार्क का बोझ नहीं ढोया जायेगा. इस बार 'बिम्सटेक' के दोस्तों को तरजीह दी गयी. इस संगठन की सामरिक तथा आर्थिक उपयोगिता चीन की प्रतिद्वंद्विता का मुकाबला करने के संदर्भ में तो है ही, दक्षिण-पूर्व एशिया के उन देशों के साथ राष्ट्रीय हितों का समायोजन करने में भी है, जिनकी आबादी का बहुसंख्यक हिस्सा इस्लाम के अनुयाइयों का है. यह दक्षिण एशियाई मुसलमानों के दिलो-दिमाग से पाकिस्तान का असर मिटाने का प्रयास है. बांग्लादेश और मलेशिया के मुसलमानों की संख्या यदि इंडोनेशिया तथा भारत के मुसलमानों के साथ जोड़ दी जाये, तो पाकिस्तान का कद बौना नजर आता है. 'बिम्सटेक' के अलावा उज्बेकिस्तान एवं किर्गिस्तान जैसे शंघाई सहकार संगठन के मित्र राष्ट्रों को भी बुलाया गया था. इन देशों की पहचान इस्लामी ही है, परंतु यह सऊदी-सुन्नी कट्टरता से मुक्त हैं. ये शिया नहीं हैं, पर ऐतिहासिक रेशम राजमार्ग पर स्थित होने के कारण ईरान के करीब हैं. उसे अपना शत्रु नहीं समझते हैं.

> जयशंकर और डोभाल दोनों ही (अति) यथार्थवादी हैं तथा पाकिस्तान एवं चीन के साथ प्रतिद्वंद्विता का निर्वाह नेहरूयुगीन आदर्शवादी अदूरदर्शिता के साथ नहीं करना चाहते.

शपथ-ग्रहण के तत्काल बाद हुए मंत्रालयों के आवंटन में चौंकानेवाला फैसला यह था कि पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया. चूंकि, सुषमा स्वराज ने सेहत की वजह से चुनाव नहीं लड़ा था, तो ये अटकलें लगायी जा रही थीं कि इस बार यह मंत्रालय किसी और को मिलेगा. कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि विदेश सेवा के एक अवकाशप्राप्त अधिकारी को यह जिम्मेदारी मिलेगी. जयशंकर विलक्षण प्रतिभाशाली हैं, साथ ही प्रधानमंत्री के विश्वासपात्र भी. उन्होंने अमेरिका और चीन में भारत के राजदूत के रूप में काम किया है. अब लाल-बुझक्कड़ी इस बात को लेकर जारी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से उनके संबंध कैसे रहेंगे? कई लोग यह मानते हैं कि गुप्तचर संगठन में काम कर चुके डोभाल को विदेश मंत्रालय के अधिकारी अपना समकक्ष नहीं मानते तथा प्रधानमंत्री पर उनके प्रभाव के कारण ईर्ष्यादग्ध रहते हैं. जयशंकर को काबीना मंत्री बनाये जाने के तत्काल बाद डोभाल की भी पदोन्नति हो गयी है तथा यह ऐलान किया गया है कि वह पांच साल तक इस पद पर बने रहेंगे. यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि प्रधानमंत्री की इस भरोसेमंद जोड़ी में कोई दरार पड़ सकती है. इसके पहले भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं और उनकी सलाह से ही विदेश नीति संचालित हुई है.

जहां तक सैद्धांतिक मतभेद का सवाल है, जयशंकर और डोभाल दोनों ही (अति) यथार्थवादी हैं तथा पाकिस्तान एवं चीन के साथ प्रतिद्वंद्विता का निर्वाह नेहरूयुगीन आदर्शवादी अदूरदर्शिता के साथ नहीं करना चाहते. अमेरिका के साथ घनिष्ठता के बारे में दिवंगत साम्यवादी पार्टियों के अतिरिक्त सर्वदलीय सहमति है. संकट इस बात का है कि अमेरिका की हर इच्छा को पूरा करने के बाद इसके एवज में कुछ हासिल करने के लालच में भारत ठोकर खा सकता है. मसलन, ईरान पर अमेरिका द्वारा अंकुश लगाने से हमारे उभयपक्षीय संबंधों में तनाव. मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाने में चीन की रजामंदी अमेरिकी कृपाकटाक्ष से संभव हुई, यह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है. अमेरिका और चीन के बीच अभी वाणिज्य युद्ध जारी है. भारत को यहां भी सतर्क रहने की जरूरत है. अफगानिस्तान के दलदल में फंसने से बचने की जरूरत है. अमेरिका के लिए 'अफ-पाक' क्षेत्र संवेदनशीलता है, हमारे लिए प्राथमिकताएं दूसरी हैं. बृहत्तर भारत का जो क्षेत्र हिंदू-बौद्ध-सूफी इस्लामी सांस्कृतिक विरासत का साझेदार है, वही हमारा नैसर्गिक प्रभावक्षेत्र है. दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया, मॉरीशस के अलावा विश्वव्यापी प्रवासी भारतीय हमें उन दूसरे देशों से अलग करते हैं, जिनकी हस्ती क्षेत्रीय ही हो सकती है.

देश की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां कम नहीं हैं. कट्टरपंथी आतंकवाद, माओवाद, अलगाववाद तथा इनका गठजोड़ विकास को बाधित करता रहा है. अमित शाह द्वारा गृह मंत्रालय का दायित्व संभालने के बाद इस शूल के समूल उन्मूलन के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ संयुक्त अभियान संचालित हो सकता है. नये रक्षा मंत्री पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं. भारत की अखंडता तभी निरापद रह सकती है, जब इन तीन मंत्रालयों में प्रतिस्पर्धा नहीं, परस्पर पूरक सहयोग हो. हमारी समझ में मोदी निर्वाचित प्रधानमंत्री जरूर हैं, पर उनकी कार्य-शैली अमेरिकी राष्ट्रपति सरीखी है. अपने 'नवरत्नों' का सदुपयोग करने में वह समर्थ नजर आते हैं.

पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध

अमित रंजन
रिसर्च फेलो, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर
amitranjan.jnu@gmail.com

अपने दूसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव को चुना है. वे आठ व नौ जून को मालदीव में होंगे तथा संसद को संबोधित करेंगे. वहां से लौटने के क्रम में वे नौ जून को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में रुकेंगे. भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए विचारों के आदान-प्रदान की दृष्टि से यह दौरा एक महत्वपूर्ण अवसर है. मंत्रालय का यह भी कहना है कि इन पड़ोसी द्वीपीय देशों की प्रधानमंत्री की यात्रा हमारी प्राथमिकता 'पड़ोसी पहले' (नेबरहुड फर्स्ट) की नीति तथा 'सागर' (इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा व विकास) के सिद्धांत से जुड़ी है.

हाल में संपन्न हुए संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की शानदार जीत पर सबसे पहले बधाई देनेवालों में मालदीव के नेता भी शामिल थे. वास्तव में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति और स्पीकर मोहम्मद नशीद ने एक्जिट पोल में सत्ता में उनकी वापसी की संभावना के बाद ही उन्हें बधाई दे दी थी. बतौर राष्ट्रपति अब्दुल्ला अमीन के शासनकाल (2013-2018) के दौरान मालदीव ने मुख्य रूप से चीन और सऊदी अरब से नजदीकी बढ़ायी थी तथा भारत से दूर जाने की कोशिश की थी. मालदीव में बड़े पैमाने पर चीनी निवेश भी हुए. परिणामस्वरूप, यह देश चीन के लगभग 1.5 अरब डॉलर के कर्ज में फंस गया.

सोलिह के सत्ता संभालने के तुरंत बाद चीन ने 3.2 अरब डॉलर का बिल भेजा था. हालांकि, चीन द्वारा इस बात से इनकार किया जाता रहा है. लेकिन, वह कहता रहा है कि कर्ज की यह राशि 1.5 अरब डॉलर के करीब है. मालदीव की मदद के लिए दिसंबर, 2018 में राष्ट्रपति सोलिह की दिल्ली यात्रा के दौरान भारत ने इस द्वीपीय देश को 1.4 अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की थी. उसी समय दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए अनेक समझौते भी किये थे. तब सोलिह भारतीय कारोबारियों से भी मिले थे और उन्हें मालदीव में निवेश का निमंत्रण दिया था. उस समय उन्होंने कहा था कि संयुक्त गश्ती और हवाई निगरानी के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भी दोनों पक्ष सहमत हो गये हैं.

इस साल मार्च में तत्कालीन विदेशमंत्री सुषमा स्वराज भी मालदीव की यात्रा पर गयी थीं. इस दौरे पर भी अनेक मसलों पर सहकार बढ़ाने के लिए समझौते किये गये थे, जिनमें वीजा सुविधा, विकास सहयोग और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमुख थे. वर्ष 2015 के राष्ट्रपति चुनाव में मैत्रिपाला सिरिसेना के हाथों महिंद्रा राजपक्षे की हार के बाद श्रीलंका के साथ भारत के रिश्ते तुलनात्मक रूप से बेहतर हुए हैं. मुख्य तौर पर राजपक्षे के दूसरे कार्यकाल (2010-2015) के दौरान भारतीय प्रभाव क्षेत्र से श्रीलंका की दूरी बढ़ती जा रही थी. पर, अब दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हुए हैं.

लेकिन समय-समय पर श्रीलंका से प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ राष्ट्रपति सिरिसेना के मतभेदों के समाचार आते रहते हैं तथा सिरिसेना ने अक्सर भारतीय खुफिया एजेंसियों पर उन्हें मारने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया है. अगले वर्ष जनवरी में श्रीलंका में होनेवाले राष्ट्रपति चुनाव में उनके फिर से खड़े होने की संभावना है. दशकों तक जातीय हिंसा के बाद श्रीलंका में अतिवाद में अचानक वृद्धि हुई है तथा सिंहली और मुस्लिम समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है. अप्रैल में ईस्टर के मौके पर श्रीलंका कुछ चर्चों पर सिलसिलेवार बम हमले का गवाह बना, जिसमें ढाई सौ से अधिक लोगों की जान चली गयी. कुछ रिपोर्टों में कहा गया था कि इन हमलों के मुख्य आरोपी ने कभी भारत का दौरा किया था, लेकिन जांच के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों को ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है. इन घटनाओं की वजह से सामुदायिक तनातनी बढ़ती ही जा रही है.

अपनी सामरिक स्थिति के कारण श्रीलंका भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है. ऐसे में वहां के तनावपूर्ण माहौल पर प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान चर्चा होनी स्वाभाविक है. दूसरा अहम पहलू यह है कि इस द्वीपीय देश में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है. श्रीलंका ने औपचारिक तौर पर दिसंबर, 2017 में हंबनटोटा बंदरगाह को चाइना मर्चेंट्स पोर्ट होल्डिंग्स कंपनी को 99 साल के पट्टे पर दे दिया है. इस वर्ष गहरे समुद्र में कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने के लिए श्रीलंका ने भारत और जापान के साथ एक समझौता किया है. भारत पहले ही त्रिंकोमाली को विकसित करने पर सहमति व्यक्त कर चुका है. हालांकि, 2016 के बाद से चीन द्वारा श्रीलंका को होनेवाला निर्यात भारत से अधिक हो गया है, पर उसका मुख्य कारण चीनी परियोजनाओं के लिए वस्तुओं का निर्यात है. वैसे भारत बहुत थोड़ा ही पीछे है. द्विपक्षीय आयात और निर्यात बढ़ाने की कोशिशों को भी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से बल मिलेगा. श्रीलंका में होनेवाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत का हिस्सा 16 प्रतिशत से कुछ अधिक है. व्यापारिक संबंधों के साथ इस क्षेत्र में भी बढ़त की संभावनाएं हैं.

इस तरह की घरेलू और भू-सामरिक स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव और श्रीलंका यात्रा का बहुत महत्व है. इन पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के साथ इस दौरे से भारत की सामुद्रिक नीति को भी नयी ऊर्जा मिलेगी.

> घरेलू और भू-सामरिक स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव और श्रीलंका यात्रा का बहुत महत्व है. इन पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के साथ इस दौरे से भारत की सामुद्रिक नीति को भी नयी ऊर्जा मिलेगी.

बोधि वृक्ष

ज्ञान-चक्षु

इस धरती पर मानव ही ईश्वर की एक ऐसी खुबसूरत कृति है, जो चिंतन कर सकता है. यह बौद्धिक विधा इस कायनात के किसी अन्य जीव को हासिल नहीं है. इंसान कभी जीवन के बीते दिनों और भविष्य के बारे में सोच कर हलकान होता है, तो कभी उसके जेहन में परिवार के प्रति आसक्ति और मोह-माया की तेज आंधी चलती है. आशय यह है कि इंसान ताउम्र कुछ-न-कुछ सोचता रहता है. हर पल उसके दिमाग में विचारों का तेज बवंडर चलता रहता है. काफी शिद्दत से विचार करें, तो इस सत्य को किसी आईने की तरह साफ होने में देर नहीं लगती है कि इंसान की सोच का गहरा संबंध जीवन में विविध प्रकार की समस्याओं के समाधान की खोज से होता है. यहां पर एक अहम प्रश्न यह उठता है कि आखिर एक इंसान अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए कितना सोचे? आखिर किसी समस्या के हल के लिए सोच का दायरा क्या होना चाहिए? जीवन में सोच अनिवार्य है, क्योंकि इसके गर्भ में समस्याओं के समाधान और आत्मज्ञान का भ्रूण छुपा होता है. लेकिन इस सत्य से हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं कि किसी विषय पर निरंतर सोचते रहने से समस्या और भी गंभीर हो जाती है, मानसिक शक्ति का क्षरण होता जाता है. मन आशंकाओं की अभेद्य परतों से आवृत होता जाता है और जिसकी परिणति मानसिक तनाव और अवसाद में होती है. इसलिए जीवन की समस्याओं पर बहुत सोचने की प्रवृत्ति से खुद को महफूज रखना जरूरी है. जीवन के बारे में कहा जाता है कि यह कभी ठहरता नहीं है. जीवन ठहर जाये, तो वह फिर जीवन नहीं है. जीवन चलने का नाम है. नदी की तेज बहाव के मध्य यदि कोई शिलाखंड हो, तो उससे टकराने के बाद मधुर संगीत का सृजन होता है. मानव जीवन का फलसफा भी इससे परे नहीं है. जीवन में समस्याएं ज्ञान-चक्षु खोलती हैं, स्वयं में बुद्ध का आविर्भाव करता है. लिहाजा समस्याओं पर अवश्य सोचिये, लेकिन इसकी लगाम पर आपकी पकड़ भी मजबूत होनी चाहिए.

श्रीप्रकाश शर्मा

आपके पत्र

लैंगिक समानता के लिए काम हो

लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2015 में 193 देशों ने हस्ताक्षर किये थे, जिसकी समय सीमा वर्ष 2030 रखी गयी थी. पिछले दिनों बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा इस पर समीक्षा एवं स्थिति विकास रिपोर्ट जारी किया गया. इससे ज्ञात होता है मुट्ठी भर देशों जैसे डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, जापान और जर्मनी को छोड़ कर किसी देश ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है. 120 देशों के रैंक में भारत का स्थान 95वां है. मतलब बेटी को सिर्फ देवी का दर्जा देकर हम पिछले सौ सालों से इस दिशा में तीसमार खां बने बैठे हैं. मगर पितृसत्तात्मक सोच वाली मानसिकता की जो स्थिति वर्ष 1919 में था, वही हाल वर्ष 2019 में भी है. इसमें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की एक ही कहानी है. नीति बनाने और कानून का प्रावधान कर देने से यह मनःस्थिति नहीं बदलने वाली है.

जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी,जमशेदपुर

भीषण गर्मी से त्रस्त जनजीवन

ताकतवर होने के दंभ में मनुष्य प्रकृति और पर्यावरण से जितना छेड़छाड़ कर रहा है, प्रकृति उसका उतना ही भयंकर प्रतिशोध ले लेती है. लगभग 70 वर्ष पूर्व जब भारत में जंगलों, नदियों, जलाशयों, तालाबों, बावडियों, भूगर्भीय जल की स्थिति अच्छी थी, तब गर्मी के दिनों में भी दक्षिण-मध्य भारत के कुछ शहरों का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच जाता था, लेकिन उत्तर भारत अपेक्षाकृत ठंडा रहता था. आज राजस्थान का चुरू शहर का तापमान 50डिग्री सेल्सियस तक और लखनऊ तक का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है. अंतरराष्ट्रीय संस्था एल्डराडो वेदर वेबसाइट द्वारा जारी विश्व के सबसे गर्म 15 शहरों में 10 भारत में और 5 पाकिस्तान में स्थित है. हर साल पिछले साल से ज्यादा गर्मी होने का रोना रोते हैं परंतु गर्मी इतनी भीषण और विकट क्यों होती जा रही है, इस पर कभी भी गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया जाता. हमें, हमारे समाज और हमारी सरकारों को ईमानदारी से और गंभीरतापूर्वक इस विषय पर काम करना होगा.

निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने की जरूरत

आज के समय में विद्यार्थियों को कक्षा एक से अष्टम तक तो पढ़ाई करने में उतनी परेशानी नहीं होती, परंतु नवम में जाते ही उनकी परेशानी शुरू हो जाती है क्योंकि अचानक सिलेबस बढ़ जाता है. यह एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से विद्यार्थी खुद को उस परिस्थिति में ढाल नहीं पाते और उनकी कुछ कड़ियां कमजोर रह जाती हैं. ऐसा लगता है कि अष्टम और नवम् के सिलेबस में साइंस को छोड़ कर और किसी विषय का लिंक ही नहीं है. इसलिए इस शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने की जरूरत है. सिलेबस को बेहतर तरीके से तैयार करने की जरूरत है ताकि विद्यार्थियों को पढ़ने में दिक्कत न हो. इस परेशानी को विद्यालय के प्राचार्य और सभी विषयों के शिक्षक ही दूर कर सकते हैं, बशर्ते कि वे अपने छात्रों की मुश्किलों को समझ सकें.

नयन कुमार सिंह, इमेल से

कुछ अलग

गरमी से लड़ने के तौर-तरीके

क्षमा शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार
kshamasharma1@gmail.com

गरमी से हाहाकार है. कहीं पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है. दोपहर में सड़कों पर कर्फ्यू सा लगा है. चुरू राजस्थान में पारा 50 डिग्री तक जा पहुंचा है. कानपुर ने गरमी का दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. लोग गरमी से बचने के लिए शीतल पेय और आइसक्रीम का सहारा ले रहे हैं.

भारत एक गरम देश है, इसलिए पुरखों ने गरमी से निपटने के तरह-तरह के तरीके भी ईजाद किये थे. घर की रसोई संभालने वाली स्त्रियों को इसकी जानकारी थी. गरमी के दिनों में खाली पेट कभी बाहर न निकला जाये. छाछ का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाये. सौंफ, खरबूजे के बीज गुलाब की पंखुड़ियों और काली मिर्च की ठंडाई दूध में मिलाकर पी जाये. फालसे का शर्बत पिया जाये. मौसमी फल जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज का इस्तेमाल किया जाये. खीरा, ककड़ी या खरबूज खाली पेट कभी न खाये जायें. इन्हें खाने के बाद पानी कभी न पिया जाये. कच्ची अमिया, चीनी, पोदीना, भुने जीरे से बना पना और दही की लस्सी का प्रयोग किया जाये. लू से बचने के लिए घर से बाहर निकलते वक्त खूब पानी पीकर निकला जाये. सिर ही नहीं शरीर के अन्य अंग भी ढका जाये. गरमी से लौटकर तत्काल पानी न पिया जाये. पंखे के नीचे खड़े होकर पसीना न सुखाया जाये, जिससे ठंडा-गरम न हो जाये. इन दिनों एक पंखे का विज्ञापन कहता है कि पंखे के नीचे खड़े होकर जल्दी से पसीना सुखा लिया जाये, यानी कि विज्ञापन बनानेवालों को भी हवा में पसीना सुखाने के दुष्परिणाम नहीं मालूम हैं.

अक्सर पुरानी बातों को पिछड़ा कहकर खारिज कर दिया जाता है, जबकि यह सच नहीं होता है. कठिनाइयों, रोगों और मौसम की आपदाओं से लड़ने के तरीके पीढ़ियों के अनुभव जन्य ज्ञान से निकलते हैं. ज्ञान एक तरह से आजकल कहे जानेवाले क्लीनिकल ट्रायल जैसे होते हैं. इन ट्रायल्स में भी दवाओं के असर को मरीज के अनुभव जन्य ज्ञान से ही मिलाया जाता है, बल्कि डॉक्टर भी दवा लिखने से पहले मरीज से तकलीफ और अनुभव को ही पूछते हैं. सिर्फ खान-पान ही नहीं मौसम जन्य विपत्तियों से निपटने का एक तरीका हमारा पहनावा और वस्त्र भी होते हैं. इसीलिए हर जगह की पोशाकें अलग-अलग दिखती हैं.

गरमी के इस मौसम में अपने अतीत की तरफ देखना जरूरी है. हमारी माताएं, दादियां, नानियां इन दिनों हमें क्या खिलती-पिलाती थीं, क्या सलाह देती थीं. जिद करने पर भी बहुत सी चीजें खाने को मना करती थीं और कहती थीं कि अगर खाओगे तो बीमार पड़ोगे. अक्सर उनका कहा सच भी होता था. गरमी में अक्सर रात के वक्त हल्का खाना खाने की सलाह दी जाती थी. डॉक्टर आज भी यही कहते हैं जिससे कि गरमी से परेशान हमारा पाचनतंत्र रात में और परेशान न करे. हम चैन की नींद सो सकें. मुड़कर बुजुर्गों की सीख के बारे में सोचिये और गरमी से अच्छी तरह से निपटिये.

देश दुनिया से

हिंद महासागर में प्रभुत्व जमाना चाहता है भारत

अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत हिंद-प्रशांत रणनीति के आधार स्तंभ हैं. लेकिन वर्तमान में, यहां इस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ी भारत की भूमिका गायब है. ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल अपेक्षाकृत छोटा है और वह लगभग 60,000 पूर्णकालिक सक्रिय-कर्मियों के साथ इस क्षेत्र में मौजूद है. जापान यहां 23 अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मेजबानी करता है. जापान के 300,000 सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज के सक्रिय और रिजर्व कर्मी यहां तैनात हैं, जिनमें से अधिकांश पूर्वोत्तर एशिया में हैं. शांगरी-ला संवाद में, अमेरिकी रक्षा सचिव पैट्रिक शैनहान ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसके 370,000 से अधिक सर्विस मेंबर हैं. हालांकि, एक बड़ी तैनाती के बावजूद अमेरिका अभी तक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शीत युद्ध जैसा अर्ध-गठबंधन बनाने में विफल रहा है. अमेरिका, चीन को नियंत्रित करने के लिए भारत का उपयोग करना चाहता है, लेकिन वह हिंद महासागर में नयी दिल्ली की महत्वाकांक्षा से सावधान है. भारत अपने प्रभाव क्षेत्र में अमेरिका को कदम को नहीं रखने देगा. असल में भारत की इच्छा हिंद महासागर पर प्रभुत्व जमाने की है. इस महत्वाकांक्षा की सबसे बड़ी बाधा अमेरिका है, चीन नहीं.

GLOBAL TIMES

कार्टून कोना

साभार :कार्टून मूवमेंट

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है